शोध पर आधारित वैश्विक रैंकिंग में चीन ने अमेरिका को कैसे पीछे छोड़ दिया? भारतीय विश्वविद्यालयों को भी इससे कुछ सबक लेने होंगे।

हरिवंश चतुर्वेदी

विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा में अमेरिका और यूरोपीय देशों का दबदबा रहा है। दुनिया में शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से साल-दर-साल ये पता चलता है कि उनमें से कौन ऊँचाइयों की ओर बढ़ रहा है और कौन रैंकिंग की फिसलपट्टी पर फिसल रहा है। जिन प्रमुख विश्वविद्यालय रैंकिंगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय माना जाता है, वे हैं—टाइम्स हायर एजुकेशन, क्यू एस और शंघाई एआर वू रैंकिंग। इन सभी रैंकिंगों के प्रमुख आधार शिक्षण गुणवत्ता, अनुसंधान, उद्योगों से तालमेल, प्लेसमेंट, एलुमनाई की गुणवत्ता माने जाते हैं।

अभी एक सप्ताह पहले वैश्विक स्तर पर ग्लोबल रैंकिंग में एक धमाका हुआ है। अभी तक पिछले 4 दशकों से चला आ रहा अमेरिकी आइवी लीग यूनिवर्सिटीयों का दबदबा टूटता नजर आ रहा है। यह धमाका नेदरलैंड्स के लीडन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग ने किया है, जो कि प्रमुखतः विश्वसनीय शोध और अनुसंधान पर आधारित है। लीडन रैंकिंग में शीर्षस्थ 10 विश्वविद्यालयों में चीन के जे-जियांग यूनिवर्सिटी नंबर एक स्थान पर आई है और उसने हार्वर्ड को पहले नंबर से तीसरे स्थान पर धकेल दिया है। बाकी 7 स्थानों पर भी चीन के कुछ शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों का कब्ज़ा हो गया है।

आज से 25 वर्ष पूर्व, चीन के जे-जियांग यूनिवर्सिटी शोध-आधारित ग्लोबल रैंकिंग में शीर्ष 25 स्थानों पर भी नहीं थी। आज ये विश्व में नंबर एक स्थान पर पहुँच गई है।पिछले 25 वर्षों में वैश्विक रैंकिंग में बाज़ी बिल्कुल पलट गई है। चीनी विश्वविद्यालयों ने जो कुछ कर दिखाया है, इससे आने वाले दशकों में

उच्च शिक्षा में भारी उतार-चढ़ाव के संकेत मिलते हैं। ज़रा सोचिए, हमारे अपने शीर्ष विद्यालय कहाँ खड़े हैं ?

हमें लीडन यूनिवर्सिटी, नीदरलैंड्स की शोध-आधारित ग्लोबल रैंकिंग 2025 में हुए उठा- पटक से कतई यह नहीं समझना चाहिए कि उच्च शिक्षा में वैश्विक स्तर पर अमेरिकी शीर्ष विश्वविद्यालयों का एक दम से पराभव हो गया है कि अब एक सदी से चला आ रहा हार्वर्ड, स्टैनफर्ड, व्हार्टन, येल और एम.आई.टी. प्रमुख अब नहीं रहा । मिसाल के तौर पर, हार्वर्ड के प्रोफेसर आज भी पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसर्च करते हैं, लेकिन हार्वर्ड पहले स्थान से तीसरे स्थान पर खिसक गया है। 6 अन्य अमेरिकी यूनिवर्सिटी जो प्रथम 10 यूनिवर्सिटीयों की सूची से बाहर हो गई हैं, वहाँ भी रिसर्च के कामों में कोई गिरावट नहीं आई है।

चीनी विश्वविद्यालयों की सफलता के प्रमुख कारण क्या हैं? ये रातोंरात संभव नहीं हुए है।इस के पीछे चीन की सरकार द्वारा 40 वर्षों से शोध को दी गई प्राथमिकता है। चीनीसरकार की दीर्घकालिक और भारी निवेश नीति इस सफलता का एक और प्रमुख कारणमाना जाता है। चीन में ज्यादातर विश्वविद्यालय सरकारी हैं और वे मुख्य रूप से सकरार की वित्तीय सहायता पर ही आधरित होते हैं।

चीनी विश्वविद्यालयों को केवल शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शोध इंजन के रूप में विकसित किया गया। वे अनुसंधान के लिए उद्योगो के साथ मिलकर काम करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शोधकार्यों की निर्देश किया जाता है। चीनी विश्वविद्यालयों ने अर्तराष्ट्रीय जर्नलों में बड़ें पैमाने पर प्रकाशन किये हैं। अग्रेंजी भाषा में उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्र, जिनका वैश्विक स्तर पर अधिक

सिटेशन हुआ। एक तरह से चीनी विश्वविद्यालयों की वैश्विक सफलता का कारण राष्टीय प्राथमिकता से जुड़ा शोध कार्य है जैसे मीकडक्टर, क्वान्टम टैक्नोलॉजी, बायोटेकनोलॉजी जैसे क्षेत्रों में लक्षित अनुसंधान ।

विदेशों में शोध कर रहे चीनी नागरिकों वापस चीन बुलाकर अनुसंधान करने के लिये वैश्विक प्रतिभा की आक्रामक भर्ती की गई। विदेशी और प्रवासी चीनी वैज्ञानिको कोआकर्षक पैकेज, आधुनिक प्रयोगशालाएं और शोध स्वतंत्रता दी गई। चीन का रिसर्च इकोसिक्टम और स्केल भारत की तुलना में बहुत विशाल और मजबूत है। इस की प्रमुख विशेषताएं हैं। बड़े विश्वविद्यालय, बड़े शोध समूह, साझा प्रयोगशालाएं और ठीम-आधारित

शोध संस्कृति |

क्या वैश्विक रैंकिंग में चीन की सफलता से भारत कुछ सीख सकता है। वे तो सच है कि हमारी परिस्थिति चीन से भिन्न रही हैं और दोनों देशों की राजनैतिक प्रणाली में भिन्नता हैं। हमे शोध को उच्च शिक्षा का केन्द्र बिन्दु बनाना होगा। इससे शिक्षण कार्यो में भी बहुत सुधार आयेगा। विश्वविद्यालयों में शिक्षण प्रधानता से शोध प्रधानता की ओर बदलाव लाने

के निरंतर प्रयास करने होंगे। हमे अनुसंधान में निवेश बढ़ाना होगा। अनुसंधान कर्ता शिक्षको को प्रति फैकल्टी शोध अनुदान, दीर्धकालिक और प्रतिस्पर्धी ग्रांट देनी होगी। भारत को विश्व-स्तरीय शोध इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। इसके लिये साझा प्रयोगशालाएं,रिसर्च क्लस्टर और उत्कृष्टता केंद्र बनाने होंगे। ये सब काम हमारा देश अकेले नहीं कर

पायेगा। अंर्तराष्ट्रीय सहयोग और सह-लेखन के द्वारा इसे मुमकिन करना होगा। फैकल्टी विकास और वैश्विक भर्ती भी इसमें जरूरी तरीके साबित होंगे प्रतिस्पर्धी वेतन, रिसर्च सपोर्ट, अकादमिक स्वायत्तता के क्षेत्रों में प्रगतिशील कदम उठाने होंगे। हमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े शोधकार्यों पर जोर देना होगा।

उद्योग-विश्वविद्यालय सहयोग, पेटेंट, स्टार्ट-अप और सामाजिक प्रभाव को और अधिक जोर देना होगा। चीन की तरह हमें वैश्विक ब्रांडिंग और प्रतिष्ठा निर्माण पर भी काम करना होगा। भारतीय शोध के बारे में विश्व स्तर कम पर लोग हम जानते हैं भारतीय विश्वविद्यालयों की रीय दृश्यता

बढ़ाना भी आवश्यक होगा।

चीन विश्वविद्यालयों ने जो चमत्कार कर दिखाया है, वह पिछले 25 वर्षों में किए गए अथक परिश्रम का नतीजा है, जिसे चीनी सरकार का पूर्णजोर समर्थन मिलता रहा है। चीन ने इन वर्षों में जो आर्थिक तरक्की की है, उसका एक अंश वित्तीय सहायता के रूप में चीनी विश्वविद्यालयों को भी मिलता रहा है।ये विश्वविद्यालय शोध और अनुसंधान में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर कड़ी मज़बूती बनाए रखते हैं और उद्योगों से मिलकर अनुसंधान योजनाओं को अंजाम देते हैं। चीन को अगले 25 वर्षों में किन चुनौतियों से जूझना है, उन पर वे अभी से रिसर्च करने में लगे रहते हैं।

चीनी विश्वविद्यालयों की ग्लोबल रैंकिंग में सफलता से यह कतई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालयों में इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के अंतर्गत अनुसंधान उत्कृष्टता और वैश्विक जुड़ाव को भारतीय उच्च शिक्षा के रूपांतरण का एक स्तंभ माना गया

है। पिछले दशक में अंतरराष्ट्रीयकरण, फैकल्टी और विद्यार्थी का आदान-प्रदान और पीएचडी के संयुक्त निर्देशन पर जोर दिया गया है। एन.आई.पी.- 20-20 का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 10 और 2047 तक 20 विश्व की शीर्षस्थ 200 रैंकिंगों में भारत के विश्वविद्यालयों को कम से कम दस स्थान मिल सकें।वर्ष 2016 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने एएनएआई आरएफ रैंकिंग शुरू की थी, जिससे पिछले एक दशक में शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्साहवर्धक परिणाम आए हैं।इस रैंकिंग में शोध और अनुसंधान को 30 प्रतिशत वजन दिया जाता है। परंतु अभी यह स्वैच्छिक है और केवल 40 प्रतिशत यूनिवर्सिटी और 15 प्रतिशत कॉलेज ही इसमें भाग ले रहे हैं।

भारतीय विश्वविद्यालयों को ग्लोबल रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए सरकार द्वारा वित्तीय समर्थन की प्रबल ज़रूरत होगी। शोध व अनुसंधान एक महंगा सौदा है। भारतीय बजट (2025-26) में उच्च शिक्षा पर ₹50,067 करोड़ का आबंटन किया गया था, जिसमें रिसर्च पर आंशिक तौर पर खर्च रखा गया था। इसमें प्रमुख रूप से अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन को ₹2,000 करोड़ आबंटित किया था।प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना पर भी ₹1,660 करोड़ वार्षिक व्यय का प्रावधान रखा गया। ये माना जाना चाहिए कि अनुसंधान पर अधिक वित्तीय कोष आबंटित किए जा रहे हैं, किन्तु इस तथ्य से इनकार नहीं करना चाहिए कि ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा और रिसर्च -आधारित रैंकिंग के लिए नाकाफी हैं।